आरबीआई की मौद्रिक नीति बैठक शुरू

7 अक्टूबर को आएगा ब्याज दरों पर फैसला, 25 बेसिस पॉइंट बढ़ोतरी का अनुमान

नवभारत न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर. भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की तीन दिवसीय बैठक सोमवार से शुरू हो गई। समिति महंगाई, आर्थिक वृद्धि और वित्तीय परिस्थितियों की समीक्षा करेगी.



ब्याज दरों पर फैसला 7 अक्टूबर को आएगा. इस बार रेपो दर को लेकर बाजार की नजर खास तौर पर बनी हुई है. महंगाई के दबाव, कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और रुपए में कमजोरी के बीच दरों में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है. रॉयटर्स के सर्वेक्षण में करीब 60 प्रतिशत अर्थशास्त्रियों ने रेपो दर में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी का अनुमान जताया है. यदि ऐसा होता है तो रेपो दर 5.25 प्रतिशत से बढ़कर 5.50 प्रतिशत हो जाएगी. 2025 में आरबीआई ने चार बार में कुल 1.25 प्रतिशत की कटौती की थी. इसके बाद 2026 में अब तक हुई चार बैठकों में दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

कर्ज महंगा, एफडी पर फायदा संभव– रेपो दर बढ़ने का सीधा असर बैंकों की कर्ज लागत पर पड़ सकता है. बैंक इसका बोझ ग्राहकों पर डालते हैं तो होम लोन, कार लोन और व्यक्तिगत कर्ज की ब्याज दरें बढ़ सकती हैं. इससे नई ईएमआई महंगी होने के साथ फ्लोटिंग रेट वाले मौजूदा कर्ज की ईएमआई या अवधि भी बढ़ सकती है.

दूसरी ओर, बैंक जमा आकर्षित करने के लिए सावधि जमा की ब्याज दरों में भी बढ़ोतरी कर सकते हैं. ऐसे में एफडी करने वाले ग्राहकों को ज्यादा ब्याज मिलने की संभावना रहेगी. हालांकि, दरों में वास्तविक बदलाव बैंक अपनी जमा और कर्ज लागत के हिसाब से तय करेंगे. आरबीआई के सामने इस समय महंगाई को नियंत्रित रखने और आर्थिक वृद्धि की रफ्तार बनाए रखने के बीच संतुलन की चुनौती है.

बढ़ती महंगाई पर नजर

एसबीआई रिसर्च ने भी इस बैठक में 25 बेसिस पॉइंट बढ़ोतरी की संभावना जताई है. रिपोर्ट के मुताबिक बढ़ती महंगाई, कमजोर तरलता और वैश्विक स्तर पर बढ़ते जोखिम आरबीआई के लिए चुनौती बने हुए हैं. भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में और बढ़ोतरी का खतरा भी ब्याज दर के फैसले को प्रभावित कर सकता है .जापानी ब्रोकरेज फर्म नोमुरा का अनुमान है कि अक्टूबर और दिसंबर में रेपो दर में 25-25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हो सकती है. ऐसा होने पर दर 5 .75 प्रतिशत तक पहुंच सकती है.

अस्पतालों में 10 अरब डॉलर का विदेशी निवेश

- निजी अस्पतालों में इलाज 5 से 10 गुना महंगा
- इलाज की बढ़ती लागत बनी चिंता

नवभारत न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर. भारत के अस्पताल कारोबार में विदेशी निवेश तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ इलाज की बढ़ती लागत को लेकर अस्पतालों और बीमा कंपनियों के बीच टकराव भी बढ़ गया है. ब्लैकस्टोन, केकेआर, टीपीजी और जनरल अटलांटिक जैसे वैश्विक निवेशकों ने पिछले पांच वर्षों में भारतीय अस्पताल श्रृंखलाओं में करीब 10 अरब डॉलर का निवेश किया है.

इस पूंजी से नए अस्पताल, महंगी चिकित्सा तकनीक और अस्पतालों के विस्तार को गति मिली है. दूसरी ओर, इलाज महंगा होने और मरीजों पर बढ़ते खर्च को लेकर सवाल उठ रहे हैं. ईवाई के आंकड़ों के आधार पर सामने आई जानकारी के मुताबिक, निजी इक्विटी निवेशकों की हिस्सेदारी देश के कुल अस्पताल बेड में अभी 5 प्रतिशत से कम है, लेकिन इनका प्रभाव हृदय रोग, कैंसर जैसे ज्यादा मार्जिन वाले विशेषज्ञता वाले इलाज में तेजी से बढ़ा है. निवेशकों के लिए भारत का अस्पताल क्षेत्र इसलिए आकर्षक है क्योंकि देश में अस्पताल बेड की उपलब्धता अभी भी जरूरत के मुकाबले कम है और गंभीर बीमारियों के इलाज की मांग लगातार बढ़ रही है.



इलाज की लागत पर बढ़ा विवाद

बीमा कंपनियों का आरोप है कि कुछ निजी अस्पताल मरीजों को महंगी प्रक्रियाओं की ओर ले जा रहे हैं, जिससे बीमा दावों और इलाज की लागत दोनों में वृद्धि हो रही है . अस्पताल संचालकों का कहना है कि बीमा कंपनियों से भुगतान में देरी और कम प्रतिपूर्ति दरों के कारण उनके परिचालन मार्जिन पर दबाव है . मेडिकल महंगाई 13 प्रतिशत सालाना तक पहुंचने की बात संसदीय रिपोर्ट में सामने आई है . वहीं, सांसदों के एक पैनल के मुताबिक निजी अस्पतालों में इलाज की लागत सरकारी व्यवस्था की तुलना में औसतन पांच से 10 गुना तक अधिक हो सकती है .

कंज्यूमर कंपनियों में इनोवेशन का दावा, आरएंडडी पर खर्च कम

- कंपनियां आरएंडडी के बजाय मार्केटिंग पर ज्यादा निर्भर
- वैश्विक कंपनियों से मुकाबले के लिए बढ़ाना होगा तकनीकी निवेश

नवभारत न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर. भारतीय कंज्यूमर कंपनियां लगातार नए उत्पाद, बेहतर तकनीक और इनोवेशन की बात कर रही हैं, लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी आरएंडडी पर उनका खर्च इस दावे के अनुरूप नहीं बढ़ रहा.

कंपनियां बाजार में नए उत्पाद उतारने, ब्रांड मजबूत करने और ग्राहकों तक पहुंच बढ़ाने पर बड़ा निवेश कर रही हैं, जबकि नए उत्पादों के विकास और तकनीकी शोध के लिए खर्च अपेक्षाकृत सीमित है.

इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, कंज्यूमर सेक्टर में काम करने वाली कई प्रमुख कंपनियों का आरएंडडी खर्च उनके कुल कारोबार की तुलना में काफी कम है. ऐसे समय में जब भारतीय कंपनियां वैश्विक बाजार में विस्तार और अंतरराष्ट्रीय ब्रांडों से मुकाबले की तैयारी कर रही हैं, रिसर्च पर कम खर्च लंबे समय में प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को प्रभावित कर सकता है.

कंज्यूमर कंपनियों के कारोबार में ब्रांडिंग, विज्ञापन, वितरण नेटवर्क और नए बाजारों में पहुंच बनाने पर भारी खर्च किया जाता है. इसका सीधा असर बिक्री और बाजार हिस्सेदारी पर दिखाई देता है.

मेड इन इंडिया को बनाना होगा भरोसे का ब्रांड

लागत के दम पर नहीं, गुणवत्ता और नवाचार से बनेगी वैश्विक पहचान : श्रीनिवासन

नवभारत न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली , 5 अक्टूबर. भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन वैश्विक बाजार में मजबूत पहचान बनाने के लिए अब केवल कम लागत पर उत्पादन पर्याप्त नहीं होगा.

भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता ऐसी होनी चाहिए कि दुनिया के किसी भी बाजार में 'मेड इन इंडिया' नाम भरोसे की गारंटी माना जाए. टीवीएस मोटर कंपनी के चेयरमैन एमेरिटस और इंडियन फाउंडेशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट के चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन ने भारत के सामने गुणवत्ता को लेकर मौजूद इस चुनौती को रेखांकित किया है. आईएफक्यूएम के वार्षिक संगोष्ठी-2026 में श्रीनिवासन ने कहा कि भारत ने गुणवत्ता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन अभी भी देश को लंबा रास्ता तय करना है. वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बढ़ने के साथ भारतीय कंपनियों को अपने उत्पादों और प्रक्रियाओं की गुणवत्ता में लगातार सुधार करना होगा. उनका कहना था कि भारत की वैश्विक पहचान केवल इस आधार पर नहीं बन सकती कि यहां उत्पाद सस्ते तैयार होते हैं. दुनिया को यह भरोसा होना चाहिए कि भारतीय उत्पाद गुणवत्ता, विश्वसनीयता और टिकाऊपन के मामले में भी श्रेष्ठ हैं.

लागत से आगे बढ़ने की जरूरत



श्रीनिवासन के मुताबिक, भारत यदि 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य हासिल करना चाहता है तो उसे लागत आधारित प्रतिस्पर्धा से आगे बढ़ना होगा. वैश्विक कंपनियां ऐसे बाजारों में निवेश और कारोबार को प्राथमिकता देती हैं, जहां उत्पादों की गुणवत्ता और आपूर्ति व्यवस्था पर भरोसा किया जा सके . इसलिए भारतीय उद्योग के लिए गुणवत्ता सुधार अब केवल कंपनियों का आंतरिक विषय नहीं, बल्कि देश की वैश्विक आर्थिक पहचान से जुड़ा मुद्दा है .

ईएसआईसी में आधार वैलिडेशन जरूरी

नवभारत न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर. कर्मचारी के ईएसआईसी पंजीकरण के बाद आधार वैलिडेशन की प्रक्रिया समय पर पूरी करना जरूरी है. कर्मचारी के पंजीकरण के 30 दिन के भीतर नियोक्ता को यह प्रक्रिया पूरी करनी होती है. इसके लिए ईएसआईसी नियोक्ता पोर्टल पर लॉगिन कर कर्मचारी के आधार का बायोमेट्रिक वैलिडेशन किया जा सकता है. सबसे पहले नियोक्ता को ईएसआईसी की वेबसाइट पर जाकर नियोक्ता लॉगिन करना होगा. यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा भरकर लॉगिन करने के बाद न्यू आईपी आधार वैलिडेशन विकल्प चुनना होगा. इसके बाद कर्मचारी का कर्मचारी कोड दर्ज कर सर्च करना होगा.

दिसंबर तक तीन देशों से निवेश समझौते की तैयारी

- दिसंबर तक कम से कम तीन समझौते अंतिम करने का लक्ष्य
- रूस समेत कई देशों के साथ बातचीत जारी

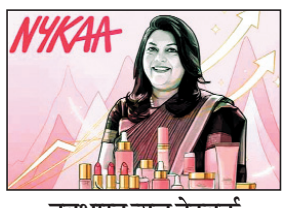
नवभारत न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर. भारत दिसंबर तक कम से कम तीन और देशों के साथ द्विपक्षीय निवेश संरक्षण समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में बताया कि रूस समेत कई देशों के साथ इस संबंध में बातचीत चल रही है.

सरकार का जोर ऐसे समझौतों के जरिए दोनों देशों के निवेशकों के लिए निवेश का सुरक्षित और भरोसेमंद माहौल तैयार करने पर है. सीतारमण के मुताबिक, बातचीत आगे बढ़ने की स्थिति में दिसंबर तक कम से कम तीन देशों के साथ समझौते अंतिम रूप ले सकते हैं. द्विपक्षीय निवेश संरक्षण समझौते में निवेशकों के हितों की सुरक्षा, निवेश से जुड़े विवादों के समाधान और सीमा-पार निवेश के लिए नियमों को अधिक स्पष्ट बनाने जैसे प्रावधान शामिल होते हैं. भारत की यह पहल ऐसे समय में है, जब सरकार विदेशी निवेश बढ़ाने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में देश की भागीदारी मजबूत करने पर जोर दे रही है. निवेश संरक्षण से जुड़े समझौतों को विदेशी कंपनियों के लिए नियामकीय भरोसा बढ़ाने के एक माध्यम के तौर पर देखा जाता है.

नायका फैशन कारोबार में सबसे आगे

सितंबर तिमाही में कुल नेट रेवेन्यू 27-29% बढ़ने का अनुमान



नवभारत न्यूज नेटवर्क

मुंबई, 5 अक्टूबर. ब्यूटी और फैशन कारोबार करने वाली नायका की मालिक एफएसएन ई-कॉमर्स वेंचर्स ने सितंबर तिमाही के कारोबार को लेकर मजबूत वृद्धि का अनुमान जताया है.

कंपनी के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में उसका समेकित नेट रेवेन्यू पिछले साल की समान अवधि की तुलना में करीब 27-29 प्रतिशत बढ़ सकता है. सकल बिक्री मूल्य यानी जीएमवी में भी इतनी ही वृद्धि का अनुमान है, जबकि नेट सेल्स वैल्यू में 31-33 प्रतिशत बढ़ोतरी की संभावना है. कंपनी के कारोबार में फैशन खंड की वृद्धि ब्यूटी कारोबार से तेज रही. सितंबर तिमाही में फैशन कारोबार के एनएसवी में 47-49 प्रतिशत और नेट रेवेन्यू में 41-43 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है.

ब्यूटी कारोबार भी स्थिर

ब्यूटी कारोबार के एनएसवी और नेट रेवेन्यू में 27-29 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है . कंपनी के अनुसार नए ग्राहकों के जुड़ने के साथ पुराने ग्राहकों की दोबारा खरीदारी से भी कारोबार को सहारा मिला . सितंबर तिमाही में नायका ने 14 नए स्टोर जोड़े . 30 सितंबर तक कंपनी के कुल स्टोर की संख्या बढ़कर 338 हो गई .

ओमान बना भारत का सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर

नवभारत न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर. भारत के तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) आयात परिदृश्य में सितंबर के दौरान बड़ा बदलाव देखने को मिला. ओमान भारत का सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा और उसने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया. यह बदलाव ऐसे समय में आया है जब भारत पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनावों के बीच अपने ऊर्जा आयात स्रोतों में विविधता लाने की रणनीति पर लगातार काम कर रहा है. ऊर्जा विश्लेषण कंपनी क्प्लर के आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर में भारत ने ओमान से 5.85 लाख टन एलएनजी का आयात किया, जो अगस्त की तुलना में 11.6 प्रतिशत अधिक था. इसके साथ ही भारत के कुल एलएनजी आयात में ओमान की हिस्सेदारी 27 प्रतिशत रही.

- सितंबर में अमेरिका को छोड़ा पीछे

जीएसटी में गिरफ्तारी के नियम बदलने की योजना

- जीएसटी के 24 अपराधों के प्रावधान नरम करने पर विचार
- नौ अपराध हटाने और 11 को मौजूदा रूप में रखने का प्रस्ताव

नवभारत न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर. जीएसटी व्यवस्था में कारोबारियों को बड़ी राहत देने वाले बदलावों पर विचार किया जा रहा है.

जीएसटी परिषद की 7 अक्टूबर को होने वाली बैठक में कर अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्तियां खत्म करने और गिरफ्तारी के लिए अदालत की मंजूरी अनिवार्य करने के प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है.



इसके साथ ही कर चोरी से जुड़े मामलों में आपराधिक मुकदमा शुरू करने की सीमा एक करोड़ रुपए से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है. प्रस्ताव लागू होने पर पांच करोड़ रुपए तक की कर चोरी को आपराधिक कार्रवाई से बाहर रखा जा सकता है.

सोना-चांदी आयात पर भी फैसला

बैठक में सोना, चांदी और प्लैटिनम के आयात पर बैंकों और नामित एजेंसियों को मिलने वाली एकीकृत जीएसटी छूट खत्म करने के प्रस्ताव पर भी विचार हो सकता है . फिलहाल इन धातुओं के आयात पर तीन प्रतिशत जीएसटी लगता है, लेकिन बैंकों और सरकार से मान्यता प्राप्त एजेंसियों को 2017 से छूट मिली हुई है .

समाचार विशेष

एमएलसी चुनाव : राज परिवार की एंट्री

- भाजपा के 'गुरुजी' या सपा के शशांक किसका बदलेगा गणित?

आगरा, 5 अक्टूबर. उत्तर प्रदेश विधान परिषद शिक्षक और स्नातक एमएलसी चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है. प्रत्याशी जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुट गए हैं. आगरा खंड स्नातक सीट पर इस बार सियासी तस्वीर बेहद दिलचस्प होने जा रही है.

इस सीट पर अवागढ़ रियासत के राज परिवार ने एंट्री की है. जिससे भाजपा, सपा और कांग्रेस के खेमे में खलबली मच गई है. इस सीट पर भाजपा ने मौजूदा एमएलसी अलीगढ़ के मानवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ 'गुरुजी' पर दोबारा से दांव लगाया है, तो सपा ने एटा के शशांक यादव को प्रत्याशी बनाया है. आगरा स्नातक एमएलसी सीट पर राज परिवार के सदस्य निर्दलीय अमरीश पाल सिंह की एंट्री और अन्य मजबूत निर्दलीय प्रत्याशियों की वजह से भाजपा और सपा के उम्मीदवारों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है. आगरा स्नातक और शिक्षक दोनों ही सीट पर राजा बलबंत सिंह शिक्षण संस्थान की अहम भूमिका रहती थी. आरबीएस शिक्षण संस्थान से स्नातक और शिक्षक दोनों ही एमएलसी के लिए मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी होती है. इस शिक्षण संस्थान के सचिव व अवागढ़ रियासत के राज परिवार के सदस्य अमरीश पाल सिंह इस बार एमएलसी चुनाव में निर्दलीय मैदान में उतरे हैं. चर्चा है कि अमरीश पाल सिंह पहले भाजपा से टिकट के प्रयासरत थे. मगर, पार्टी ने मौजूदा एमएलसी मानवेंद्र प्रताप सिंह पर भरोसा जताया. इसपर अमरीशपाल सिंह ने निर्दलीय ताल ठोकी है. अमरीश पाल सिंह की दावेदारी से भाजपा का गणित बिगड़ सकता है. क्योंकि, अवागढ़ रियासत के राज परिवार की आगरा, एटा, अलीगढ़, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, फिरोजाबाद, मथुरा, कासगंज और हाथरस जिले में गहरी पैठ है.



'गुरुजी' पर भाजपा का दोबारा दांव

मानवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ 'गुरुजी' पर भाजपा ने दोबारा दांव लगाया . आगरा खंड शिक्षक और खंड स्नातक विधान परिषद (एमएलसी) के निर्वाचन क्षेत्र में आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, इटावा, फर्रुखाबाद, कासगंज, हाथरस, औरैया और कन्नौज जिले आते हैं . विधानसभा से अलग और रोमांचक है चुनाव - निर्दलीय उम्मीदवार अमरीश पाल सिंह ने बताया कि जितना बड़ा क्षेत्र होता है . उतनी बड़ी चुनौती भी होती है . मैं और मेरी टीम लंबे समय से क्षेत्र में एक्टिव हैं .

वीआईटी भोपाल यूनिवर्सिटी का सातवां वार्षिक दीक्षांत समारोह संपन्न

3,571 को मिलीं डिग्रियां, 21 मेधावी को गोल्ड मेडल

नवभारत कनेक्ट

सीहोर, 5 अक्टूबर. वीआईटी भोपाल यूनिवर्सिटी का 7वां वार्षिक कन्वोकेशन शनिवार को उत्साह और गरिमापूर्ण माहौल में संपन्न हुआ. इस अवसर पर विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षणिक संकाय के कुल 3 हजार 571 ग्रेजुएट्स को डिग्रियां प्रदान कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई.



समारोह में पूर्व चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, इंडियन आर्मी और 'ऑपरेशन सिंदूर' के आर्किटेक्ट रिटायर्ड जनरल उपेंद्र द्विवेदी चीफ गेस्ट के रूप में शामिल हुए। वहीं, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर (इन-स्पेस), डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के प्रमोशनल डायरेक्टर डॉ. विनोद कुमार ने गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में शिरकत की. कार्यक्रम का शुभारंभ वीआईटी भोपाल यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉ. जी. विश्वनाथन, वाइस प्रेसिडेंट डॉ. शंकर विश्वनाथन, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट मिस कादंबरी एस. विश्वनाथन, ट्रस्टी मिस रमणी बालासुंदरम, वाइस चांसलर प्रो. सतीश कुमार मोढ़, रजिस्ट्रार डॉ. ज्ञान प्रकाश मिश्रा एवं प्रो वाइस-चांसलर डॉ. टी. बी. श्रीधरन की गरिमामयी उपस्थिति में हुआ. कार्यक्रम की शुरुआत विनम्रता और शैक्षणिक उत्कृष्टता की परंपराओं की प्रतीक शैक्षणिक जुलूस के साथ हुई। यह जुलूस ऑडिटोरियम में पहुंचा। दीक्षांत समारोह में अलग-अलग विषयों के 3 हजार 571 ग्रेजुएट्स को डिग्रियां दी गईं, जिनमें 3 हजार 62 बीटेक, 72 एमटेक, 156 इंटीग्रेटेड एमटेक, 30 एमबीए, 142 एमसीए, 48 बीबीए, 3 बीआर्क, 12 बीएससी, 8 एमएससी ग्रेजुएट्स और 38 पीएचडी स्टूडेंट्स शामिल थे.

मोना मिश्रा का प्रयोग कितना कामयाब होगा?

लखनऊ, 5 अक्टूबर. करीब डेढ़ दशक के बाद कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में महिला प्रदेश अध्यक्ष बनाया था. पहला प्रयोग बहुत कामयाब नहीं रहा था. 2007 से 2012 तक रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस की अध्यक्ष थीं. बाद में वे समाजवादी पार्टी से होते हुए भाजपा में चली गईं.

इसके बाद कांग्रेस ने 2017 के चुनाव में भी शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बना कर चुनाव लड़ने की तैयारी की. जुलाई 2016 में उनके नाम की घोषणा भी हो गई थी. हालांकि बाद में समाजवादी पार्टी के साथ तालमेल हो गया तो इस योजना को स्थगित कर दिया गया. फिर भी इसमें कोई दो राय नहीं है कि महिला और ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष बनाने का एक असर उत्तर प्रदेश में हो सकता है. कांग्रेस यह दावा कर सकती है कि वह महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने और बड़ी जिम्मेदारी देने वाली पार्टी है.



विशेष | अंबुमणि रामदास से सीक्रेट बातचीत

एनडीए को झटका देगी विजय की पार्टी?

चेन्नई, 5 अक्टूबर.तमिलनाडु की राजनीति में एक बार फिर बड़े सियासी बदलाव के संकेत मिल रहे हैं. मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) और पट्टाली मक्कल कच्ची के बीच संभावित गठबंधन को लेकर चर्चाएं तेज हो गईं हैं. मुताबिक, दोनों दलों के बीच बातचीत अब शुरुआती संपर्क से आगे बढ़कर सत्ता में भागीदारी और कैबिनेट पदों तक पहुंच गई है. हालांकि, अभी तक किसी औपचारिक गठबंधन की घोषणा नहीं हुई है.

पीएमके ने 2026 के विधानसभा चुनाव में एआईएडीएमके-भाजपा गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा था और



पार्टी ने 18 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे. लेकिन अब 6 अक्टूबर को होने वाले मदुरंतकम और धारापुरम उपचुनाव में पीएमके ने किसी भी दल का समर्थन नहीं करने का फैसला किया है. खासकर मदुरंतकम में पार्टी का यह रुख महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यहां उसका पारंपरिक वन्नियार वोट बैंक एआईएडीएमके को फायदा पहुंचा सकता था.

अंबुमणि और विजय के सलाहकार के बीच बातचीत- जानकारी मुताबिक, पीएमके की ओर से अंबुमणि रामदास और टीवीके की ओर से विजय के राजनीतिक सलाहकार जॉन अरोकियास्वामी के बीच बातचीत चल रही है. दोनों के बीच राजनीतिक संपर्क पुराना बताया जाता है. अरोकियास्वामी ने 2016 के विधानसभा चुनाव के दौरान पीएमके की रणनीति पर भी काम किया था. टीवीके से जुड़े सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि विजय सरकार में पीएमके को दो कैबिनेट पद देने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई है. इनमें एक पद अंबुमणि रामदास की पत्नी और विधानसभा में पीएमके की फ्लोर लीडर सौम्या अंबुमणि को तथा दूसरा पद पार्टी विधायक ए. गणेश कुमार को दिए जाने की चर्चा है. हालांकि, इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक फैसला सामने नहीं आया है.

सौम्या अंबुमणि के पास मजबूत चुनावी जनादेश-सौम्या अंबुमणि ने धर्मपुरी विधानसभा सीट पर 93,713 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी. उन्होंने इस चुनाव में टीवीके उम्मीदवार को 20,896 वोटों से हराया था. यही वजह है कि संभावित सत्ता साझेदारी की चर्चाओं में उनका नाम प्रमुखता से सामने आ रहा है.

उपचुनाव के नतीजों पर टिकी बातचीत

टीवीके के एक वरिष्ठ नेता के हवाले से कहा गया है कि उपचुनाव के नतीजे पीएमके के साथ बातचीत की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं . टीवीके का प्रदर्शन मजबूत रहने पर विजय के पास बातचीत में अधिक मजबूत स्थिति हो सकती है, जबकि कमजोर प्रदर्शन की स्थिति में बाहरी सहयोगियों की अहमियत बढ़ सकती है . पीएमके का सबसे मजबूत आधार वन्नियार समुदाय के बीच माना जाता है, जिसका प्रभाव उत्तरी तमिलनाडु के कई हिस्सों में है .